JAGRAN CITY PAGE I

स्नातक कालेज के शिक्षकों को पीएचडी कराने की मंजूरी

लविवि की आनलाइन विद्या परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास

जासं, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध राजकीय एवं एडेड स्नातक महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले अर्ह शिक्षक भी पीएचडी करा सकेंगे। अभी तक पीजी के शिक्षक ही शोध कराते हैं। शनिवार को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से बड़ी संख्या में पात्र शिक्षकों को शोध कराने का मौका मिलेगा।

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने बताया कि राजकीय व एडेड स्नातक महाविद्यालयों में शिक्षकों के पीएचडी कराने के लिए इसके आर्डिनेंस-2020 में बदलाव करना होगा। विद्या परिषद से इसे मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव बनाकर राजभवन को भेजकर बदलाव की अनुमति ली जाएगी। जून में कुलपति ने डीन एकेडमिक प्रो. राकेश चंद्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कालेजों के सुझाव और कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है।

लविवि शुरू करेगा डीलिट की पढ़ाई: लविवि जल्द ही डाक्टर आफ लिटरेचर (डीलिट)/ डाक्टर आफ साइंस (डीएससी) कोर्स की शुरुआत करेगा। विद्या परिषद में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। कुलपति के मुताबिक, इसके लिए आर्डिनेंस बनाया चुका है, लेकिन कोर्स की समय सीमा को लेकर राजभवन से पूछा गया था। अब तय हो गया है कि डीलिट का कोर्स कम से कम एक वर्ष और अधिकतम दो वर्ष का होगा। आर्डिनेंस में इस संशोधन के करके मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। जैसे ही वहां से अनुमति मिली, इसमें प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसमें कितनी सीटें होंगी, यह भी आर्डिनेंस में शामिल है।

अभिनव गुप्त संस्थान बनेगा संकाय: लविवि में करोड़ों की लागत से बने अभिनव गुप्त शोध संस्थान अब संकाय बनेगा। इसमें रिसर्च से लेकर कई नए कोर्स भी शुरू होंगे। कुछ माह पहले इसका नया भवन बनवाया गया था। बीते मार्च में उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने उद्घाटन भी किया था।

पीएचडी में सुपर न्यूमैरिक कोटे के लिए बनेगी कमेटी: अभी तक लविवि में सभी शिक्षकों के लिए पीएचडी कराने की संख्या तय है। जब विदेशी छात्र पीएचडी के लिए आते हैं तो किस शिक्षक के पास कितने छात्र पीएचडी कर सकते हैं, यह नहीं तय है। इन्हें अतिरिक्त माना जाता है। बीते दिनों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस संबंध में एक पत्र भेजा था। इस आधार पर कुलपति ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है।

इन पर भी फैसला

- न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के अनुसार पुनर्विचार के लिए संकाय परिषदों को वापस भेजा जाएगा।
- लविवि में डीफर्मा, बीफर्मा पाठ्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर।
- कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कला एवं शिल्प, आइएमएस, ओएनजीसी केंद्र के संकाय परिषद एवं बोर्ड आफ गवर्नेंस से संस्तुत पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।
- पीएचडी वायवा आनलाइन लेने के लिए डीन स्तर से मिलेगी अनुमति।
- कला संकाय में दो विभागों संस्कृत एवं दर्शनशास्त्र में पीएचडी छात्रों का पुनः आवंटन।
- इंस्टीट्यूट आफ न्यू एंड रेनेवल एनर्जी को प्रशासन योजना का अनुमोदन।
- इंजीनियरिंग संकाय में बीसीए में 60 से 120 सीट एवं बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को मंजूरी।
- जून-2021 में शोध प्रबंध (थीसिस) जमा न कर पाने वाले शोधार्थियों को दिसंबर तक मौका।

भूले पंजीकरण संख्या, फंसे प्रवेश पत्र

बीएड प्रवेश परीक्षा

संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पंजीकरण संख्या ही भूल गए, जिसकी वजह से प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन पर संपर्क किया, जिसके बाद अधिकारियों ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए विस्तृत निर्देश भी जारी किए।

राज्य समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेयी ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपना बीएड 2021-23 की पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अंकित करना होता है। आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या उसे, उसकी ई-मेल पर प्रेषित की गई थी। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश पंजीकरण संख्या भूल गए हैं, वे अपनी ईमेल, जिसे उन्होंने अपने बीएड 2021-23 के आवेदन पत्र में भरा था, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि उन्हें इस ई-मेल से पंजीकरण संख्या नहीं मिल रही तो उन्हें ई-मेल helplineupbedw8wv@gmail.com पर अपना विवरण भेजना होगा। पंजीकरण संख्या उन्हें इसी ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

i-NEXT PAGE 4

ऑनर्स कोर्स भी होने लगे डिजाइन

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिलेबस में किया जा रहा बदलाव

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW(17July):लखनऊ यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोर्सों को तैयार करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है. वहीं आनर्स कोर्सों को डिजाइन करने का काम भी शुरू हो गया है. कोर्सों की नए सिरे से संरचना करते समय सर्वाधिक ध्यान इसका रखा जा रहा है कि वे अधिक से अधिक रोजगार परक साबित हों.

शोध में आधुनिक विषय

नई शिक्षा नीति के अनुसार समाज शास्त्र, इतिहास जैसे विषयों में भी रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है. पूरी कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स समाज की जरूरतों को देखें और उसमें बदलाव लाने के लिए कुछ करें. समाज शास्त्र में गुलाबी गैंग, इम्युनिटी से लेकर डायटिंग तक की प्रवृति पर शोध किया जा रहा है. वहीं इतिहास विषय में आधुनिक महामारी और मध्यकाल में आई बीमारियां आदि शामिल हैं. बीमारियां आदि. पीजी के स्टूडेंट अब फ्लैक्सिबल एंट्री और एक्जिट विभिन्न अंत: और अंतर विभागीय कोर्स, इंटर्नशिप आदि का फायदा उठा सकते हैं. इसी क्रम में ग्रेजुएशन के कोर्सों में नई शिक्षा नीति के पहलुओं को शामिल करने का काम लगभग पूरा हो गया है.

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

कॉलेजों के स्नातक शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी

लविवि की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया अहम निर्णय

माई सिटी रिपोर्टर

लाखनऊ। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के राजकीय और एडेड महाविद्यालयों के सभी नियमित शिक्षक भी पीएचडी करा सकेंगे। शनिवार रात संपन्न हुई लविवि की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।

पिछले काफी समय से इन महाविद्यालयों के स्नातक के शिक्षक पीएचडी कराने की मांग कर रहे थे। अभी तक केवल पीजी के शिक्षकों को ही अनुमति थी। इस निर्णय के बाद स्नातक के शिक्षकों में भी खुशी की लहर है।

इसके अलावा बैठक में डीलिट, डीएससी व एलएलडी को संचालित करने की भी मंजूरी दे दी गई। पीएचडी के बाद पढ़ाई जारी रखने वालों को लाभ मिलेगा। अभी इसमें सीटें तय नहीं हैं। इसका ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है। कुछ शंकाएं थीं जिनको बैठक में दूर कर लिया गया है। राजभवन को ऑर्डिनेंस भेजकर पास करा लिया जाएगा। वहीं जून 2021 तक जिन पीएचडी के छात्रों ने थीसिस जमा नहीं कराई उनको एक और अवसर देते हुए दिसंबर तक जमा करने का मौका दिय गया है। कोरोना के चलते छात्र हित को देखते हुए उनको यह अवसर दिया गया। न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लेकर बैठक में काफी गर्मा-गर्मी रही।

इन मुद्दों व प्रस्तावों पर भी लिया गया निर्णय

- न्यूनतम समान पाठ्यक्रम से संबंधित शासनादेश 13 जुलाई के अनुसार पुनर्विचार करने के लिए संकाय परिषदों को भेजना।
- कला संकाय के दो विभागों संस्कृत और दर्शनशास्त्र में पीएचडी के लिए छात्रों का पुर्नआवंटन।
- कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कला एवं शिल्प, आईएमएस, ओएनजीसी केंद्रके संकाय परिषद एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रमों पर अनुमोदन।

- इंजीनियरिंग संकाय के बीसीए में सीट संख्या 60 से 120 करना।
- बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को मंजूरी।
- इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में डी फार्मा और बीफार्मा पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी।
- पीएचडी में ऑनलाइन वाइवा वायस के संबंध में निर्णय के लिए संकायाध्यक्षों को अधिकृत करने का निर्णय।
- अभिनव गुप्त संस्थान में नयी शैक्षिक गतिविधियों की रूपरेखा और संकाय के रूप में उच्चीकरण के शासन के पत्र को अनुमोदन देना।
- इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इनर्जी को प्रशासन योजना का अनुमोदन देना।

प्रो. बृजेंद्र विज्ञान संकाय के अध्यक्ष

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रो. बृजेंद्र सिंह को विज्ञान संकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति की अध्यक्षता में शनिवार को वरिष्ठता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि अभिलेखों के आधार पर अनंतिम रूप से पूर्व स्थापित वरिष्ठता 10 सितंबर 2001 को ही वर्तमान में माना है। (माई सिटी रिपोर्टर)

NBT PAGE 8

बीएड परीक्षा: दो दिन में 2,78,917 अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र

■ एनबीटी, लखनऊ: लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से महज दो दिन में 2,78,917 अभ्यर्थियों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 30 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 5,91,305 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

परीक्षा 30 को, 5,91,305 अभ्यर्थियों ने करवाया पंजीकरण

एलयू प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव के मुताविक, प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को वेवसाइट पर बीएड 2021-23 की पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अंकित करना होता है। आवेदन पत्र भरते समय पंजीकरण संख्या अभ्यर्थी को उनके ई-मेल पर भेजी की जाती है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अपने बीएड प्रवेश परीक्षा की पंजीकरण संख्या भूल गए हैं, वे अपनी ई-मेल, जिसे उन्होंने आवेदन पत्र में भरा था, से भी हासिल कर सकते हैं। ई-मेल से भी पंजीकरण संख्या नहीं मिल रही है तो वे ई-मेल helplineupbed2021@gmail.com पर अपना विवरण भेजें।

i-NEXT PAGE 4

साइंस डिपार्टमेंट के हेड बने बृजेंद्र सिंह

विज्ञान संकाय के अध्यक्ष के रूप में प्रो. बृजेंद्र सिंह को नियुक्ति दी गई है. वरिष्ठता समिति की बैठक में कंप्यूटर अभिलेखों के अनुसार सिंह की वरिष्ठता को देखते हुए उनको यह जिम्मेदारी दी गई है. उल्लेखनीय है कि यह मामला तब चर्चित हो रहा था जब नियुक्ति में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा था.

JAGRAN CITY PAGE I

प्रो. बृजेंद्र सिंह बने विज्ञान संकाय के अध्यक्ष

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने कम्प्यूटर साइंस विभाग के शिक्षक प्रो. बृजेंद्र सिंह को विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष बना दिया। शनिवार को कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठता समिति की बैठक हुई। इसमें प्रो. बृजेंद्र को विवि के अभिलेखों के आधार पर विज्ञान संकायाध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की स्वीकृति दी। (जासं)

VoL PAGE 7

बृजेंद्र बने कम्प्यूटर विभाग के डीन

लखनऊ। लखनऊ विश्व विद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के वरिष्ठता का मामला सुलझ गया। कुलपति ने शनिवार को बृजेंद्र सिंह को विभागाध्यक्ष पद का लेटर जारी कर दिया है। कंप्यूटर साइंस विभाग के बृजेंद्र सिंह विभाग में सबसे वरिष्ठ थे लेकिन उन्हें विभागाध्यक्ष न बनाते हुए कनिष्ठ प्रोफेसर को यह पद थमा दिया गया था। वरिष्ठता के लिए बृजेंद्र सिंह ने पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत कीए जहां से लखनऊ विश्वविद्यालय को नोटिस जारी हुई थी और उन्हें एलयू प्रशासन को दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। माना जा रहा है कि आयोग की कार्यवाही के बाद एलयू ने आनन.फानन में बृजेंद्र सिंह को कार्यभार दिया।

AAJ PAGE 3

हायर एजुकेशन में नये आयाम स्थापित करेगी नई शिक्षा नीति-प्रो. आलोक कुमार राय

➲विश्वविद्यालय केवल परीक्षा कराने वाले बोर्ड नहीं ➲उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में इनका अहम रोल

(मनोज गुप्ता)

लखनऊ, शनिवार। भारतवर्ष को यदि शिक्षा का उद्गम स्थल कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया इस बात को न सिर्फ जानती है बल्कि मानती भी है कि संस्कृति का सर्वप्रथम विकास भारतवर्ष में ही हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में मानवसभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ। जब दुनिया के अधिकांश देशों में सामान्य संस्कृति का भी विकास नहीं हुआ था वे कबीलों में रह रहे थे, उस वक्त भारतवर्ष में ज्ञान के प्रचार-प्रसार व शोध कार्यों के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जा रही थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय तो ईशा से पूर्व स्थापित हो चुके थे जबकि रत्नागिरि विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पुष्पागिरि व सोमपुरा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी एक हजार वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। इन विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया से लोग गणित, संस्कृत, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत समेत तमाम विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारा अतीत इतना गौरवशाली रहा लेकिन कालांतर में हम गुलाम हुए और धीरे-धीरे पिछड़ते चले गये। गुलामी के दंश से बाहर निकलने के बाद हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किये हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है पूरे देश के शिक्षाविदों ने इसका स्वागत किया है इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय का कहना है कि नई शिक्षा नीति देश की उच्च शिक्षा को पूरी तरह से बदल देगी और इस क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगी। उनका कहना है आज हमारे विश्वविद्यालय एक बोर्ड की तरह परीक्षा कंडक्ट कराने तक ही सीमित रह गये हैं जबकि विश्वविद्यालयों का काम शोध और तकनीकि का विकास कराना है। प्रो. राय का कहना है कि नई शिक्षा नीति से न सिर्फ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि विश्वविद्यालयों का स्तर भी बढ़ेगा। पेश है लविवि में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने वाले कुलपति प्रो. राय से बातचीत के कुछ अंश......

Q- लविवि अपके कार्यकाल में शताब्दी वर्ष मना रहा है, वह कौन सी उपलब्धियां जो इस वर्ष में विवि हासिल करने जा रहा है?

A- लविवि ने डेढ़ वर्ष के अपने कार्यकाल में संतोषजनक प्रगति की है विवि के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर विवि में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इस दौरान 18 नये सेल बनाये गये हैं जो कार्यपरिषद से भी पास हो चुके हैं।

Q- केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति आपने विवि में लागू की है इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कितना लाभ होगा?

A- नई शिक्षा नीति से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शोधपरक, रोजगार परक पाठ्यक्रमों को आसानी से लागू किया जा सकता है। इसी क्रम में लविवि इसी सत्र से स्नातक पाठ्यक्रमों में आनर्स प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है,जो कि पूरे भारत में यूजी में आनर्स प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा।

Q- आपके पास लविवि के साथ-साथ सम्पूर्णानन्द विवि के कुलपति का चार्ज रहा। वर्तमान में लविवि के कुलपति के साथ आगरा विवि का चार्ज है,आप दोनों चार्ज के बीच कैसे सामंजस्य बैठाते हैं?

A- लविवि के साथ-साथ सम्पूर्णानन्द विवि और आगरा विवि के कुलपति के अतिरिक्त चार्ज से उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन सिस्टम को समझने में काफी मद्द मिली। जैसे लविवि रेजिडेंसियल विवि है यहां कैम्पस में लगभग 20 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं जबकि आगरा में ऐसा नहीं है यहां पर कॉलेजों के मुद्दे अहम हैं।

Q- लविवि ने अन्य जिलों के कॉलेजों को भी सम्बद्धता प्रदान करनी शुरू कर दी है इससे लविवि को क्या लाभ मिलेगा शैक्षिक या वित्तीय?

A- उच्चशिक्षा का प्रचार-प्रसार ही हमारा लक्ष्य है। लविवि अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है इसका लाभ अब पांच अन्य जिलों को भी होगा ,जहां तक वित्तीय फायदे की बात है तो जब हमारा दायरा बढ़ेगा तो निश्चित ही हम आत्मनिर्भर भी होंगे।

Q- लविवि रेजिडेंसियल विवि होने के बावजूद सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर आश्रित है। आपके कार्यकाल में विवि का वित्तीय घाटा कितना कम हुआ है?

A- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विवि का वित्तीय घाटा लगभग 32 करोड़ था जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 21 करोड़ रह गया और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह महज 9.25 करोड़ रह गया है। इसके लिए विवि ने अपनी आय बढ़ायी है और खर्चों में कटौती की है जिससे यह सम्भव हो पाया है।

Q- विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीचिंग और नान टीचिंग कर्मचारियों के वेलफयेर के लिए क्या कदम उठाये हैं?

A- पिछले डेढ़ वर्ष में 83 में से 79 प्रमोशन किये गये हैं, कर्मचारियों के लिए आवास बनाये जा रहे हैं जिनमें से अक्टूबर तक 48 फ्लैट मिल जायेंगे। इसके अलावा मृतक आश्रितों को भुगतान किया जा रहा है और पिछले दो महीनों में 19 लोगों को मृतक आश्रित में नौकरी दी गयी है।

Q- लविवि अपनी शिक्षा के लिए विदेशों में काफी प्रसिद्ध रहा है वर्तमान में विवि में कितने विदेशी छात्र हैं?

A- शैक्षिक वर्ष 2019-20 में महज 52 विदेशी छात्र थे, 2020-21 में 149 थे जो कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष-2021-22 में 357 छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

Q- विवि में शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

A- पिछले डेढ़ वर्षों में शोध कार्य में एक तिहाई से ज्यादा की वृद्धि हुई है। शैक्षिक वर्ष 2018-19 में 653 पब्लिकेशन थे और लगभग पौने छह करोड़ की रिसर्च ग्रांट थी, शैक्षिक वर्ष 2019-20 में लगभग साढ़े चार करोड़ की रिसर्च ग्रांट थी और 654 पब्लिकेशन थे जबकि वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2020-21 में साढ़े छह करोड़ से ज्यादा कि रिसर्च ग्रांट है व 926 पब्लिकेशन हुए है।

Q- लविवि में शिक्षकों के लगभग 40 प्रतिशत पद खाली हैं ऐसे में छात्रों की पढ़ाई कहीं न कहीं प्रभावित होती है, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

A- राजभवन से शिक्षकों की भर्ती के लिए नई प्रक्रिया आयी है उसके पहले हम शीघ्र ही शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन देने जा रहे हैं। जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा उनमें उन अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी जो पहले आवेदन कर चुके हैं। विवि के पोर्टल पर यह व्यवस्था होगी की जिन लोगों ने पहले फार्म भरे हैं वे उसी में अपडेट कर सकतें हैं।